

संपादकीय

एक देश- एक चुनाव की रहा में संख्या बनी मुद्दा

विधानसभा आ के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का सदाभूत करता है। इस अवधारणा का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवसित करना, संसाधनों को बचाना और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली बाधाओं को कम करना है। लोकसभा और राज्य के चुनाव एक साथ कराने के विभिन्न लाभ क्या हैं? एक साथ चुनाव कराना संविधान के संघीय चरित्र के विरुद्ध कैसे होगा? अन्य संसदीय लोकतंत्रों में इस सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नाएँ क्या हैं? एक साथ चुनाव कराने से वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों की एक महत्वपूर्ण राशि की बचत हो सकती है, साथ ही चुनाव प्रचार में लगाने वाला समय भी बच सकता है। एक साथ चुनाव कराने से चुनाव-संचालित नीति निर्माण का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे सरकारें अल्पकालिक राजनीतिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक योजना और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। बार-बार चुनाव कराने से मतदाता थक सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मतदान कम हो सकता है। चुनाव के दौरान लागू की जाने वाली आदर्श आचार सहित विकास परियोजनाओं और नीतिगत निर्णयों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इन चुनावों में मौजूदा मत्रियों और विधायकों का समय बर्बाद होता है, क्योंकि उन्हें प्रचार के दौरान अपना ध्यान क्षेत्रीय चुनावों पर लगाना पड़ता है। इससे मीडिया रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण समय भी नष्ट हो जाता है, जो सार्वजनिक नीतियों की जांच करने के बजाय चुनाव जीतने वाले लोगों पर चर्चा करने में व्यस्त रहता है। इसलिए, कुल मिलाकर, इन चुनावों में समय और धन की कुल हानि हुई है। देश- एक चुनाव से जुड़े विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का भेज दिया गया है, जिस पर अब विचार विमर्श होगा क्यों कि यह विधेयक पारित कराने के लिये लोकसभा एवं राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है, जो मौजूदा परिस्थितियों में सत्तासीन एनडीए के पास नहीं है।

विश्व ध्यान दिवसः आत्म साक्षात्कार और विश्व शांति की ओर एक कदम

युक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर से विश्व ध्यानदिवस मनाने वाली एक ऐतिहासिक कदम है। दूरअसल मेंटिशन या ध्यान सदियों से केवल आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन

सदय स कवल आधात्म स जाड़कर दखा जाता था। लब आज वैज्ञान ने यहसिद्ध कर दिया है कि मेडिटेशन का सकारात्मक प्रभाव केवल मानव के मन या मस्तिष्क हीनहीं उसके तन पर भी पड़ता है। इसलिए 21 जून योग दिवस मनाए जाने के बाद सम्पूर्ण विश्व में अब 21 दिसंबर को ध्यान दिवस केरूप में मनाने का उद्देश्य योग की हीभावति ध्यान को जन-जन तक पहुंचाना। इसे मानव जीवन के अधिन्न अंग के रूप मेंस्थापित करके एक स्वस्थ विश्व नींव मजबूत करना है। वस्तुतः वर्तमान युग में जब मनुष्य तेजी से भागदें और उत्तरात्मक स्वास्थ्य को संतुलित करने का एक सहज, सरल प्राकृति साधन बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य सेजु समस्याएं आज वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बन गई। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 280 मिलियन लोग मानसिक रूपसे पीड़ित हैं और 40वा युवा तनाव और मानसिक अस्थिरता का सामना रहे हैं। खास बात यह है कि ध्यान, एक साधारण लेकिनशक्तिशाली प्रक्रिया, समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती है। अध्ययनों ने यह सिकिया है कि ध्यान मस्तिष्क मेंोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक रसायनों के स्तर को बढ़ाता है, जो तनाव को कम करते हैं और मूड को स्थिर रखते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, केवल अपनी साह के ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क के ग्रेमेटर में बढ़ देखी गई, जो सीख याददाश्त और भावनात्मक विनियम में सहायक है। इस प्रकार विभिन्न शोधों यह बात वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध हो चुकी है कि ध्यान केवल मनुष्य आधात्मिक उत्तर का साधन नहीं है, बल्कि नियमित रूप से इसका अभ्यास उसके जीवन के हर पहलू को समृद्ध कर सकता है।

ध्यान के वैज्ञानिक आधार को समझने के लिए न्यूरोसाइम मासिक एग शो पर ध्यान देना आवश्यक है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में किए गए ए अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि नियमित ध्यान मस्तिष्क के अमिगडला (भय और तनाव कांकड़ है) की गतिविधि को कम करता है, जिससे व्यंत तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और संतुलितबना रहता है। ध्यान के इन वैज्ञानिक लाभों को अब विभिन्न चिकित्साक्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। कई अस्पताओं और स्वास्थ्य केंद्रों अब ध्यान को मानसिक स्वास्थ्य उपचार का हिस्सा बना रहे हैं। कैसर, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए ध्यान को सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जन-आंफकिलनिकल साइकॉलजी में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया था कि ध्यान से न केवल मरीजों के दर्द की अनुभूति कम होती है, बल्कि उनमें इलाज प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान के प्रभाव को भी अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जारहा है। एक अध्ययन के अनुसार ध्यान नियमित रूप से करने से हृदय की गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे हृदय रोगों का जोखिम 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है। इसके अलावा, ध्यान प्रतिरक्षा प्रणालीको भी मजबूत करता है, जिससे शरीरीयों से सेलड़ने में अधिक सक्षम बनता है। इतना ही नहीं रिसर्च में यह बताया गया है कि ध्यान काप्रभाव के बल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं होता। जो एक व्यक्ति ध्यान करता है, तो वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक दिखाने में केंद्रित करता है, जिसका असर उसके आस-पास के वातावरण पर भी पड़ता है। कई अध्ययनों ने यह साबित किया है कि सामूहिक ध्यान के द्वारा अपराध दर में दर में गिरावट, सामाजिक सौहार्द में वृद्धि और पर्यावरणीय सामंजस्य जैसे सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। 1993 में वाशिंगटन डी.सी. में किए गए एक शोध में पाया गया कि सामूहिक ध्यान के द्वारा शहर में अपराध दर में प्रतिशत की गिरावट आई। मेडिटेशन जैसे एक सरल माध्यम से मानव आचरण में इस प्रकारके मूलभूत बदलाव इसकी वैज्ञानिकता (मनोवैज्ञानिकता) का प्रमाण है। मेडिटेशन के इन्हीं सकारात्मक प्रभावों को अपनी कार्य संस्कृति में शामिल कर रही हैं। गूगल, एप्पल, 3 माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए नियमित ध्यान सत्र आयोजित कर रही हैं। आज के प्रतिस्पर्धी के दौर में हमारे बच्चे भी पढ़ने में अपने प्रदर्शन को लेकर तनाव में रहते हैं।

सांसद भी बिजली चोरी करेंगे तो आम जनता पर क्या असर होगा?

नज़रिया

संभल से समाजगादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्दहमान बर्क के खिलाफ गुलवार को यहाँ दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। देर रात उन पर एफआई की कार्रवाई होने के बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई और बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का लगा जुर्माना टोक दिया। पुलिस ने बताया कि उनके पिता पर भी बिजली विभाग द्वारा घर के निरीक्षण के दौरान सरकारी अधिकारियों को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का

अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिजली विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई है। बिजली विभाग ने इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच बृहस्पतिवार सुबह बर्क के आवास पर निरीक्षण शुरू किया था। बर्क उन लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 24 नवंबर को संबल में हुई हिंसा के सिलसिले में भी मामला दर्ज किया गया है।



अशाक भाट्या
हर के कोट गवीं इलाके में अदालत के आदेश
पर मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के
सर्वेक्षण का विरोध करने पर सुरक्षाकर्मियों ने
साथ हुई झड़प में चार स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी। बक्सर
ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की
अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज
प्राथमिकी रख करने की भी मांग की है। बर्क्स पर 24 नवंबर
को लोगों को भड़काने का आरोप है। पुलिस ने आरोप
लगाया है कि सर्वेक्षण के दौरान हुई हिस्सा का कारण उनके
भड़काऊ भाषण था। रिट याचिका में सांसद ने खुद को
निर्देश बताते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया
है। उनके वकील के अनुसार, वह घटना स्थल पर मौजूद
नहीं थे, फिर भी उन्हें प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है।
इस बीच, बिजली विभाग के निरीक्षण के दौरान सरकारी
अधिकारियों को धमकाने के आरोप में सांसद के पिता के
खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस अधीक्षक (संभल) कण्ठ कुमार बिश्नोई ने

संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सांसद के आवास पर दादो किलोवाट के दो कनेक्शन और 10 किलोवाट का सोलर पैनल है। उन्होंने कहा कि हालांकि, उपयोग और उपकरणों के आधार पर आवश्यकता आठ से 10 किलोवाट के बीच होनी चाहिए। सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कासिम जमाल ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि निवास में चार किलोवाट के दो कनेक्शन, 10 किलोवाट का सोलर पैनल और पांच किलोवाट का जनरेटर है। ‘सेटअप’ में दो ‘एयर कंडीशनर’, 6-7 ‘सीलिंग फैन (छत वाले पंखे)’, एक रोफिजरेटर और लाइट शामिल हैं। बिल बहुत कम है क्योंकि यहां परिवार के केवल चार सदस्य रहते हैं। सांसद, उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके पिता। विद्युत विभाग का निरीक्षण जारी है क्योंकि अधिकारी अनुमानित खपत के मुकाबले मौजूदा कनेक्शन का मूल्यांकन कर रहे हैं। इलाके में पुलिस, पोस्टरी और त्वरित कार्रवाई बल के जवानों की तैनाती पर अधिवक्ता ने कहा कि यह परिवार की छिक को धूमिल करने का प्रयास है।

लम्बे समय से चल रही बिजली चोरी पर इतना सब होने के बाद सांसद जियार्हमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया जा रहा है जबकि उनकों हर सुविधा मुफ्त मिलती है। सांसद को सैलरी के साथ अलग-अलग तरह के भत्ते मिलते हैं। अगर सिर्फ भत्तों को जोड़ा जाए तो वो आंकड़ा सैलरी से कहीं ज्यादा होता है। एक सांसद को हर माह 1 लाख रुपए बतार वेतन मिलते हैं। यह

मूल वेतन है। इस्के हर माह 2 हजार रुपए दिनक भत्ता, 70 हजार रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60 हजार रुपए कार्यालय व्यय भत्ता मिलता है। इसके अलावा आवास, निर्वाचन क्षेत्र पर सालाना 1,50,000 फीट कॉल की जा सकती हैं किराया मुक्त सरकारी आवास मिलता है। जिसके लिए हर साल 50,000 यूनिट बिजली मिलती है। इस तरह सिपाही भत्तों को ही जोड़ा जाए तो यह आकड़ा वेतन से कहीं अग्रणी निकल जाता है। सांसद को पास भी दिया जाता है, जो उन्हें मुफ्त रेल यात्रा करने का अधिकार देता है। वह किसी भी ट्रेन की फर्स्ट क्लास एसी या एग्जिक्यूटिव क्लास में यात्रा कर सकते हैं। सरकारी काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने पर भी सांसद को सरकारी भत्ता देने का नियम है। हर सांसद को इलाज की सुविधा भी मिलती है। सांसद किसी भी सरकारी अस्पताल या रेफर करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं तो उसका खर्च सरकार उतारता है। इतना ही नहीं सांसद को सरकारी खर्च पर सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी एक सांसद द्वारा बिजली चोरी करना न केवल आश्वर्जनक होने के साथ दुर्भाग्यरूप भी है क्युकि वित्तीय प्रभाव के अलावा बिजली चोरी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। अवैध कनेक्शन और बिजली मीटरों के साथ छेड़गढ़ से आग लग सकती है, बिजली का झटका लग सकता है और अन्य दुर्घटनाएँ हो सकती हैं जो लोगों के

जीवन और सपत्नि को खतरे में डाल सकती हैं। इसके अलावा, बिजली चोरी से अक्सर ब्लैकआउट और बिजली की कटौती होती है, जिससे अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ बाधित हो सकती हैं। बिजली चोरी का आम जनता पर भी असर काफी ज्यादा है। जो उपभोक्ता विश्वसनीय और किफायती बिजली तक पहुँचने में असमर्थ हैं, वे केरेसिन लैप या लकड़ी के चूल्हे जैसे ऊर्जा के खतरनाक और प्रदूषणकारी स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए जो घर के अंदर वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

बर्क के इस कारनामे से क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश का संभल देश का नंबर वन बिजली चोर जिला बन गया है। जनता द्वारा जहां बिजली चोरी और बिजली के बकाया भुगतान को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आ रही है। बिजली विभाग के मुताबिक संभल शहर के बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली का 123 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि संभल शहर में बिजली चोर हर महीने 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिजली चोरी कर रहे हैं। इस लिहाज से संभल देश का सबसे बड़ा बिजली चोर जिला है। लेकिन अखिल संभल ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की। संभल के बिजली चोरों ने कौन-कौन से जुगाड़ लगाए हुए हैं और कैसे संभल में बिजली चोरी का संगठित उद्योग चल रहा है। यह भी जानना जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल टस्टींग गवाही दे रही है कि उत्तर प्रदेश का जिला संभल को देश के नंबर वन बिजली चोर जिला का खिताब क्यों मिला है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के दफ्तर में घुसते ही बिजली चोरी के साक्षात् सबूत दिख गए। छत पर तो बिजली चोरी का पूरा नेटर्क ही बिछा हुआ था। जब नेता ही बिजली चोरी कर रहे हों तो आम जनता को क्या डर। पूरे संभल में बिजली चोरी का खुल्ला खेल चल रहा है। संभल में बिजली विभाग की टीमें गली-गली जाकर बिजली चोरों की पहचान कर रही हैं। बिजली विभाग के लाइनमैन खंभों पर चढ़कर बिजली चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संभल में बिजली चोरी अब इतना कॉम्पन हो चुका है कि बिजली विभाग के दफ्तर में कटिया तारों का जमघट लग चुका है। संभल के बिजली दफ्तर में कबाड़ बनकर पड़े ये तार बिजली चोरी के टूल बने हुए थे।

अंबेडकर जी सम्मान का विषय हैं फैशन का नहीं

प्रवाण गुगनाना

भा जपा का डाइएनए म प्ररभ स हा दलित
विर्मश रहा है, क्योंकि इसका मातृ
संगठन आरएसएस प्रारंभ से हैं
सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलने वाला
संगठन रहा है। इस दलित विर्मश के ही डाइएनए का
परिणाम है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही
इस देश में अबेडकर जी को 'भारत रत्न' सम्मान
मिल पाया। अबेडकर जी को कांग्रेस ने भारत रत्न
नहीं दिया, उसने तो नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहने
नेहरू जी को और इंदिरा जी की सरकार रहते
इंदिराजी को भारत रत्न दे दिया था। अबेडकर जी
संत पेरियार, महात्मा फुले, नारायण स्वामी जैसे
दलित महापुरुष संघ के प्रतिदिन होने प्रातः स्मरण
मंत्र में सम्मिलित हैं। संघ के स्वयंसेवक जो
भाजपा के कार्यकर्ता बनते हैं वे प्रतिदिन सुबह के
आज्ञे पाता स्मरण के बारे में अस्तित्व में रहते हैं।

A portrait painting of a man with dark hair and glasses, wearing a grey suit, white shirt, and red tie. He is resting his chin on his right hand and holding a book open with his left hand. The background is a neutral grey.

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। अंबेडकर को आशासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बार बार संविधान और फैशन में अंबेडकर जी का नाम रटने वाली कांग्रेस ने तो बाबा साहेब को संविधान सभा के 296 सदस्यों में अंबेडकर जी को प्रवेश तक भी न मिलने देने हेतु षड्यंत्र रचे थे। बाद में दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से वे येन केन प्रकारण संविधान सभा में प्रवेश कर पाये थे। अंबेडकर जी बंगल की जिस खुलना जैसोर सीट से संविधान सभा में पहुँचे थे वह इकहत्तर प्रतिशत हिंदू बहल थी।

देश विभाजन में कांगड़ावन प्रतिशत हिन्दू बहुल वाले क्षेत्रों को भारत में रहने देना तय हुआ था। केवल बाबासाहेब को सर्विधान सभा में घुसने से रोकने के लिए कांग्रेस ने बंगाल का यह इकहतर प्रतिशत वाला जिला पाकिस्तान को दे दिया था ताकि अबेडकर जी की सर्विधान सभा की सदस्यता रद्द हो जाए। आज अबेडकर जी का नाम फैशन में लेने वाली कांग्रेस ने तो अबेडकर जी का चित्र तक लोकसभा में नहीं लगने दिया था। संसद में, गैरकांग्रेसी सरकार बनने पर ही अबेडकर जी का चित्र लग पाया था। भाजपा ने अबेडकर जी से जुड़े पाँच स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबासाहेब लंदन में जिस घर में रहे, भाजपा सरकार ने उसका भी अधिग्रहण किया व उनके स्मारक के रूप में उसे लंदन तक में विकसित किया। भाजपा ने ही चैत्य भूमि को विकसित किया और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ स्वयं प्रार्थना करने हेतु गए। भाजपा ने दिल्ली के 26, अल्लापुर रोड को भी विकसित किया जहाँ बाबासाहेब ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। देश विभाजन की जनक कांग्रेस के सामने

किसान आंदोलनः शुरू हो चुकी है एकजुट होने की कवायद

निमल राना

जाब - हरियाणा का सामाजिक चलन वाला क्षेत्र अंदोलन धर्मी और गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा की सीमा खनारी में गत 24 दिन से आमरण अनशन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य लगाता गिरता जा रहा है। किसान नेता के स्वास्थ्य की देखरेख में लगे डॉक्टर्स उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं। डल्लेवाल 80 साल की उम्र में इन्हें दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी देखभाल में लगे डॉक्टर्स के अनुसार पहले से ही कैंसर रोग से पीड़ित डल्लेवाल के लिवर व किडनी को इस अनशन के कारण काफी नुकसान पहुँच चुका है। उनकी किडनी व लीवर की स्थिति काफी नाजुक होती जा रही है। गौरतलब है कि इसी वर्ष 13 फरवरी को पंजाब के किसान अपनी उन मांगों को पूरी करने के बादों को याद दिलाने के लिये दिल्ली जाना चाह रहे थे जो कि मोदी सरकार द्वारा तीन विवादित कृषि कानून वापस लेते समय सरकार द्वारा मानी गयी थीं। परन्तु हरियाणा सरकार ने उन्हें पंजाब सीमा से आगे बढ़कर दिल्ली पहुँचने से रोक दिया। तभी से यह किसान पंजाब - हरियाणा की खनारी व शश्वत सीमाओं पर ढेर हुये हैं और बीच बीच में दिल्ली जाने का प्रयास भी करते रहे हैं। काविल-ए-गौर है कि जब एक वर्ष से भी लंबे समय तक चले संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन ने नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी जैसे कभी न दृक्कुने की छवि बनाने वाले नेता को तीन विवादित कृषि कानून वापस लेने के लिये मजबूर कर दिया था उस समय देश के किसानों के अधिकांश संगठन एकजुट थे। और इसी किसान एकता ने केंद्र सरकार को घुटने टेकने के लिये मजबूर कर दिया था। परन्तु उस समय भी कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री मोदी यह कहने से चूके थे कि - हमरी सरकार किसानों के कल्पणा के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव, गरीब के हित में पूरी समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आईं थीं। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूरी रूप से किसानों के हित की बात हम कृषि किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कमी रही। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था। हमने बातचीत का प्रयास किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। यह बात मोदी ने तब कही थी जब कि उस समय देश के अधिकांश छोटे बड़े किसान व उनके अधिकांश संगठन एकजुट थे। परन्तु याद कीजिये उस समय भी सरकार ने अपने समर्थन में कई ऐसे संगठनों के नाम बता दिए थे जिनका नाम पहले न तो कभी सुना गया न ही वे संगठन अस्तित्व में थे। परन्तु अब 13 फरवरी 24 से किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन जिसे कि शुरू से ही संयुक्त किसान मोर्चा से पूर्व में जुड़े सभी किसान संगठनों का समर्थन हासिल नहीं है, वह सिर्फ इसी आपसी फूट के चलते लंबा खिंचता जा रहा है। यहाँ तक कि आमरण अनशन पर बैठे 80 वर्षीय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जीवन भी संकट में पड़ गया है। उधर सरकार तमाशा बनाकर बैठी है तथा किसानों की आपसी फूट को देखते हुये आंदोलन को तब तक खींचे रखना चाहती है जब तक किसान थक हार कर आंदोलन समाप्त न कर दें या इनमें और अधिक फूट न पड़ जाये। मगर जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का सरकार पर असर पड़े या न पड़े लेकिन किसान संगठनों व विपक्षी नेताओं पर इसका प्रभाव पड़ता जरूर दिखाई देने लगा है। जहाँ विभिन्न विपक्षी राजनैतिक दलों के नेता खनारी स्थित डल्लेवाल के अनशन स्थल पर उनका स्वास्थ समाचार लेने बड़ी संख्या में पहुँचने लगे हैं वहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न धड़ों में भी हलचल तेज हो चुकी है। एस के एम के कई महत्वपूर्ण घटकों से किसान एकता के स्वर उन्हें शुरू हो चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बयान किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुये टिकैत ने कहा है कि - किसान यदि अलग-अलग चलांगे तो लुटेंगे। हमें एकजुट रहना होगा। 10 महीने पहले जब आंदोलन शुरू हुआ हमने सबको कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा और सब इकट्ठा हो जाएं।

जिलवानी ट्रेचिंग ग्राउंड में मौजूद 35 हजार 500 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है निष्पादन



समय जगत, इटारसी। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने आज नागरपालिका की टेक्नीकल टीम के साथ जिलवानी स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर हो रहे कार्यों में निरीक्षण किया। यहां मौजूद 35 हजार 500 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए कार्य चल रहा है वर्ही घरों के सैटिक टैंक से निकलने वाले मल व पानी से खाद बनाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया में बन रही खाद को देखा तो उन्हें उसमें पॉलीथिन के कण दिखे। जिस पर उहाँने नारजीकी जताई और निर्देश दिए

हैं जितनी भी खाद बनी है, उसमें से पॉलीथिन के कण देखारा से निकले इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाए। निरीक्षण के दौरान टेक्नीकल टीम की प्रमुख इंसुश्री मिनाशी चौधरी, उपर्युक्त मुकेश जैन, अदित्य पांडे, सेनिका अग्रवाल, मयंक अरोड़ा मौजूद थे।

देखें एक नजर में क्या क्या हो रहा जिलवानी में: नगरपालिका परिषद इटारसी ने घोस अपष्टि प्रबंधन के तहत इटारसी से निकलकर जिलवानी में जमा होने वाले 35 हजार 500 टन कचरे को खाद करने की योजना के तहत यहां टेंडर जारी किया हुआ है।

गवालियर की एसआर मैक्स कंपनी ने यह काम लिया है। कचरे से निकले वाले पॉलीथिन सीमेंट बनाने वाले कारखाने में टेक्नोटेक्नोलॉजीज से पॉलीथिन उपयोग हो जाने वाला प्रमाण पत्र नपा इटारसी में जमा होगा। वर्ही कचरे से खाद बनाइ जा रही है। खाद जैविक है, इसका उपयोग पार्क, खेती किसानी में हो सकता है। नगरपालिका जिलवानी में ही घरों के सैटिक टैंक से निकलने वाले अपष्टि के प्रबंधन के लिए एसटीपी बन रही है। यह कार्यों बड़ा होगा। इसमें सैटिक टैंक से निकलने वाले मल और गडे पानी को अलग अलग किया जाएगा। मल से जैविक अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद इटारसी

अवैध रेत उत्खनन में संलग्न वाहनों को किया जब्त, पुलिस ने की कार्यवाही



समय जगत, ब्लॉकरी। रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने में मुद्रित ब्लॉकरी पुलिस ने थाना प्रभागी अरुण पांडेय के नेतृत्व में फिर बड़ी कार्यवाही की है। दिनांक 19/12/24 की तारीख ब्लॉकरी पुलिस को मुखिया द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खुटेरा में अवैध रेत परिवहन कर बिक्री हेतु जे.सी.बी. मशीन द्वारा अवैध रूप से रेत हाइवा ट्रक में लोड किया जा रहा है, सूचना पर ब्लॉकरी पुलिस स्थाप द्वारा मुखियकि के बताये स्थान पर धेरबांदी कर रेड कार्यवाही की गई तो उसके बारे में अवैध देखकर जे.सी.बी. का चालक एवं ट्रायार का फायदा उठाकर पौके से फरार हो गए जिसकी आस पास तलाश किया गया नहीं मिलने पर मौके से साक्षात्कार संजय यात्रा पिता मनोज कुमार यादव अब 22 वर्ष निवासी ग्राम खुटेरा में अप.क्र. 823/24 धारा 303(2), 317(5) बीएनएस. 4/21 खान खनिज अधिनियम, 77/177 एमबीएस्ट पंजीयन कर विवेकन में लिया गया। ब्लॉकरी पुलिस द्वारा की गई उक्त कार्यवाही से अवैध रेत उत्खनन परिवहन में सलिल व्यक्तियों में भय का वातावरण निर्भित हुआ है। प्रकरण में फरार अजान आरोपियों की लाइसार तलाश जरी है। उक्त कार्यवाही एम.डी.ओ.पी. ब्लॉकरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभागी ब्लॉकरी निरी. अरुण पांडेय एवं अधीनस्थ स्थाप उन चालकरण प्रजापी, प्र.आर. 764 नेट्रन उपायाय, प्र.आर. 209 केंद्र रिंग, प्र.आर. 595 दुर्घान सिंह, आर. 642 संजय द्विवेदी, आर. 321 विलोक सिंह, आर. 803 राजीव सिंह द्वारा की गई है।

विलोक द्वारा अप.क्र. 823/24 धारा 303(2), 317(5) बीएनएस. 4/21 खान खनिज अधिनियम, 77/177 एमबीएस्ट पंजीयन कर विवेकन में लिया गया। ब्लॉकरी पुलिस द्वारा की गई उक्त कार्यवाही से अवैध रेत उत्खनन परिवहन में सलिल व्यक्तियों में भय का वातावरण निर्भित हुआ है। प्रकरण में फरार अजान आरोपियों की लाइसार तलाश जरी है। उक्त कार्यवाही एम.डी.ओ.पी. ब्लॉकरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभागी ब्लॉकरी निरी. अरुण पांडेय एवं अधीनस्थ स्थाप उन चालकरण प्रजापी, प्र.आर. 764 नेट्रन उपायाय, प्र.आर. 209 केंद्र रिंग, प्र.आर. 595 दुर्घान सिंह, आर. 642 संजय द्विवेदी, आर. 321 विलोक सिंह, आर. 803 राजीव सिंह द्वारा की गई है।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के जगह जगह चौरी छिपे हो रहे कारेबार पर भी ब्लॉकरी पुलिस ने अपनी नजरें तिरछी कर ली है गोतलब है कि अपनी पिछले सप्ताह ही 3 टैक्टर अवैध कारेबार करते बढ़ा गए थे और आज तारि एक जैवीकी मशीन को ब्लॉकरी पुलिस ने दबोच लिया है। फोन पर हुई चर्चा में नगर निरीक्षक अरुण पांडेय ने हमारे प्रतिनिधि से कहा कि जहा भी अवैध कारेबार होंगे कानून अपना काम करेगा।

नपा अध्यक्ष ने पौने 11 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों को कार्या प्रारंभ



योग अनुसंधान परिषद में प्रथम विश्व ध्यान दिवस पर शिविर का आयोजन

समय जगत, भोपाल। भारत के प्रस्ताव पर 193 देशों वाली यूएन महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस (वल्ड मेडिटेशन-डे) घोषित किया है। इस अवसर पर अज. योग अनुसंधान परिषद में प्रथम ध्यान शिविर का आयोजन किया जाएगा। परिषद महासचिव निशांत शर्मा ने कहा कि हमारी स्वस्थ रहने को पारंपरिक एवं पौराणिक कला योग के बाद ध्यान विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रही है। यूएन महासभा द्वारा घोषित दिवस पर कल कोट्या सुल्तानाबाद स्थित योग अनुसंधान परिषद में प्रता 8 से 9 बजे तक ध्यान शिविर आयोजित किया गया है। इस मौके पर गणमान्य नारायण और समानित सदस्य मौजूद रहेंगे।

ब्लॉकरी कार्यवाही के दिनेश

भद्रभदा विश्राम घाट की कार्यकारिणी हुई घोषित



राजेश बाधवानी बने वरिष्ठ उपायाय

समय जगत, भोपाल। भद्रभदा विश्राम घाट की विगत 8 दिसंबर को हुई आमसभा में सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष अरुण चौधरी ने अपनी नव नियुक्त कार्यकारिणी घोषित की। वरिष्ठ उपायाय राजेश बाधवानी, याचायश अशोक पटेल, जितेन्द्र कंसाना, संतोष बाधवी, संचिव मदेश शर्मा, संयुक्त संचिव रजनीति, त्रिपाठी, कोषायश अवज दुबे, उप कोषायश चतुर्मुख मालपानी, संस्कृत विजय चतुर्मुख ने आपस में एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया और सभी ने आगामी 5 वर्षों में विश्राम घाट में होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा बनाई एवं बधाया दी है।



- आईटी पार्क से औद्योगिक विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ नवाचार-संचालित विकास को मिलेगा बड़ावा
- आईटी पार्क का डिजाइन 'अनंत' की अवधारणा पर आधारित है जो भगवान महाकाल को दर्शाता है
- छात्रों को मिलेगी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- उज्जैन में आईटी पार्क की स्थापना से होगा समग्र शहरी और आर्थिक विकास
- आईटी कंपनियों को कम लागत में मिलेगा अधिक लाभ
- टैक कंपनियों और स्टार्ट-अप्स को एडवांस सुविधाएं